Date: 19 **जुलाई** 2023

डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक , 2023

संदर्भ:-

हाल ही में, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक , 2023 के एक मसौदे को मंजूरी दी है , जिसके लिए व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से पहले सहमति की आवश्यकता होती है और डेटा उल्लंघनों के लिए दंड लगाया जाता है विधेयक को संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

मुख्य विशेषताएं:-

प्रयोज्यता:-

- बिल ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्र किए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और डिजिटलीकरण पर लागू होता है।
- यह भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होता है यदि यह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश या व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग से संबंधित है।

सहमति:-

- व्यक्तिगत डेटा केवल वैध उद्देश्य और व्यक्तिगत सहमति के साथ संसाधित किया जा सकता है।
- सहमति मांगने से पहले नोटिस प्रदान किया जाना चाहिए , जिसमें एकत्र किए जाने वाले डेटा और प्रसंस्करण के उद्देश्य का विवरण शामिल है।
- सहमति किसी भी समय वापस ली जा सकती है।
- स्पष्ट सहमति के बिना प्रसंस्करण के लिए अपवाद में कानून के तहत कार्य , राज्य द्वारा सेवाओं का प्रावधान , चिकित्सा आपात स्थिति, रोजगार उद्देश्य और निर्दिष्ट सार्वजनिक हित उद्देश्य शामिल हैं।

डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य:-

- डाटा प्रिंसिपलों (जिन व्यक्तियों का डेटा संसाधित किया जाता है) को प्रसंस्करण के बारे में जानकारी प्राप्त करने , व्यक्तिगत डाटा में सुधार और उन्मूलन की मांग करने , प्रतिनिधियों को नामित करने और शिकायत निवारण की मांग करने का अधिकार है।
- डाटा प्रिंसिपलों के कर्तव्यों में झूठी शिकायत दर्ज नहीं करना या झूठी जानकारी प्रदान करना शामिल है।

डेटा फिड्यूशरीज के दायित्व:-

- डाटा फिड्यूशरीज (डेटा संसाधित करने वाली संस्थाएं) को डेटा सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए , उल्लंघनों को रोकने के लिए सुरक्षा सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए , और जब आवश्यक नहीं हो तो डेटा प्रतिधारण को रोकना।
- सरकारी संस्थाओं को भंडारण सीमा आवश्यकताओं से छूट है।

व्यक्तिगत डाटा का हस्तांतरण:-

- केंद्र सरकार उन देशों को सूचित करेगी जहां व्यक्तिगत डाटा को स्थानांतरित किया जा सकता है , निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

छूट:-

राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सरकारी संस्थाओं द्वारा डाटा प्रोसेसिंग के साथ-साथ अनुसंधान , संग्रह और सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए कुछ छूट मौजूद हैं। जैसे-

- अदालतों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रमुख आवश्यकताओं से व्यापक छूट प्राप्त है।
- अपराध, किसी कानून के उल्लंघन, जांच या अभियोजन के हित में संसाधित किया जा सकता है।
- भारत की संप्रभुता,एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के सन्दर्भ में।

भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड:-

- विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव है। दंड लगाने , डेटा उल्लंघनों को संबोधित करने और शिकायतों को निवारण के लिए की जाएगी।

दंड:-

- उल्लंघन की स्थिति में इस बिल में मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
- मुआवजा, दुरूपयोगकारी संस्था का अदालती मुकदमेबाजी से बचने के लिए उपाय है।
- नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित इकाई पर ₹250 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
- व्यक्तिगत अपराधों के लिए जुर्माना ₹10,000 से शुरू होगा।

आगे की राह:-

- चिंताएं मौजूद हैं कि सरकारी एजेंसियों के लिए छूट अनियंत्रित डाटा प्रसंस्करण का कारण बन सकती है और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है।
- आवश्यकता से परे डाटा संग्रह और प्रतिधारण की आनुपातिकता पर सवाल उठाया जाता है।
- यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य देशों के समान सुरक्षा उपायों के लिए सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया है।

Rajiv Pandey

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक

संदर्भ:-

हाल ही में, नीति आयोग द्वारा 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023' के नाम से रिपोर्ट जारी किया है।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में:

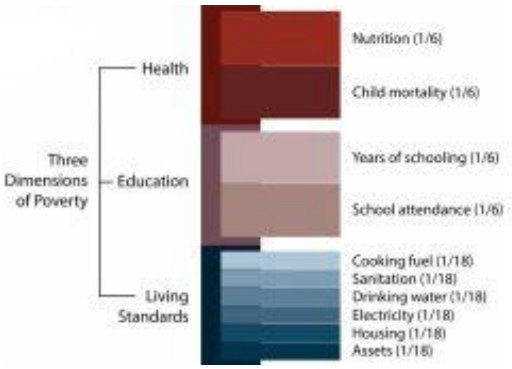

राष्ट्रीय एमपीआई तीन समान रूप से भारित **आयामों** में एक साथ अभाव को मापता **है:**

- **स्वास्थ्य:** पोषण, मातृ स्वास्थ्य और बाल और किशोर मृत्यु दर
- **शिक्षा:** स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल की उपस्थिति,
- **जीवन स्तर:** खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते।
- यह भारत में गरीबी के विभिन्न आयामों को समझने के लिए **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस - 5 (2019-21))** के आंकड़ों का उपयोग भी इसमे शामिल है।

प्रमुख बिन्दु-

भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट:

- 2015-16 और 2019-21 के बीच रिकॉर्ड5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।
- भारत ने 2015-16 में85% से 2019-2021 में 14.96% तक भारत के बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.89 प्रतिशत अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेजी से गिरावट देखी गई: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेजी से गिरावट देखी गई, जो59% से 19.28% हो गई। इसी अवधि के दौरान, शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% तक की कमी देखी गई।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान:-

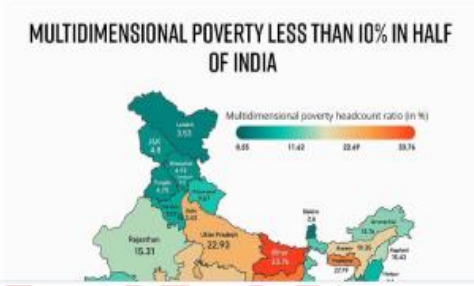

- रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेजी से कमी उत्तर प्रदेश , **बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में देखी गई।**
- **उत्तर प्रदेश** ने 43 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बचने के साथ **गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट** दर्ज की।
- **एमपीआई मूल्य में कमी:** 2015-16 और 2019-21 के बीच, एमपीआई मूल्य117 से 0.066 तक लगभग आधा हो गया **है और गरीबी की तीव्रता** 47% से घटकर 44% हो गई है।

भारत ने बहुआयामी गरीबी को इतनी तेजी से कैसे कम किया?

- नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्धारण स्वास्थ्य , शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े 12 मानकों को ध्यान में रखकर किया है , इन मानकों या पैमाने में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य से जुड़े संकेतकों को शामिल किया गया है।
- इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर , मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष , स्कूल में उपस्थिति , रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं।
- नीति आयोग का कहना है कि देश में इन सभी मानकों पर इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ है.
- उदाहरण के लिए, नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 2015-16 में लगभग 58 प्रतिशत भारतीय स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन से वंचित थे, लेकिन 2019-2021 तक, यह केवल 44 प्रतिशत था।
- इसी तरह, पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की कमी वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 51.88 प्रतिशत से घटकर 30.13 प्रतिशत हो गया, बिजली की कमी 12 प्रतिशत से घटकर 3.27 प्रतिशत हो गई, और बैंकिंग तक पहुंच से वंचित लोगों का प्रतिशत 9.66 प्रतिशत से घटकर 3.69 प्रतिशत हो गया।

समाचार स्रोत: द हिंदू

Rajiv Pandey